

Escalation in Operational Cost of F.C.I.

725. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to the disproportionate growth of the FCI and steep escalation in its operational cost most of the food-grains subsidy is drained away and that the FCI is now charging a higher margin of handling cost than officially allowed; and

(b) if so, details thereof and whether Government proposes to examine the entire functioning of the FCI to bring about allround improvement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). No, Sir. The subsidy paid to the Food Corporation of India represents the difference between the economic cost of foodgrains and the issue prices fixed by the Government. In addition, carrying charges of the national buffer are also paid to the FCI. Thus the Corporation is reimbursed the actual expenditure incurred by it for handling foodgrains for the public distribution as well as for holding the national buffer. There is no fixed margin for handling costs; it is determined every year depending upon the turnover of the Corporation.

Procurement and distribution expenses are kept under constant review for effecting economies wherever possible.

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बीज और उर्वरक

726. श्री बहाराम शक्क : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मूंगफली, सोयाबीन, सुरजमुखी और बाजें पैदा करने वाले किसानों को रियायती दरों पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उपरोक्त बीज, कितनी मात्रा में किसानों को सप्लाई किये हैं, और क्या केन्द्रीय सरकार ने भी इस प्रयोजन के लिए राज्य को अनुदान दिया है और यदि हाँ, तो उसकी राशि कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शरद० बी० स्वामीनाथन) : (क) मूंगफली तथा दलहनों के प्रमाणीकृत बीजों के मूल्य का मूल स्तर पर अर्थात् बीज उत्पादक एजेंसियों को 150/- रुपये प्रति क्विंटल तक की राज सहायता दी जाती है ताकि वे कृषकों को उचित दर पर बीज बेच सकें। सोयाबीन और सुरजमुखी के बीज पर कोई राज सहायता नहीं दी जाती है।

उर्वरकों के विद्यमान खुदरा मूल्यों में राज सहायता का हिस्सा शामिल होता है, अतः मूंगफली सोयाबीन, सुरजमुखी और दलहनों का उत्पादन करने वाले कृषकों को और रियायती दरों पर उर्वरक मुहैया कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किये गये बीज की जिलेवार मात्रा के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश के लिए मूंगफली और दलहनों के बीजों पर राज सहायता की पूर्ति हेतु 1979-80 के लिए निम्नलिखित परिव्यय स्वीकार किया गया है :—

तिलहन :

तिलहनो के परिवहन तथा संभाल की लागत की पूर्ति के लिए 1.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें मूंगफली पर 150.00 रुपये प्रति क्विंटल की राज सहायता भी शामिल है, जिसे केन्द्र और राज्य बराबर-बराबर के प्राधार पर वहन करेंगे।

दलहन :

दलहनों पर 150.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज सहायता देने के लिए 14.0 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 7.0 लाख रुपये तथा राज्य का हिस्सा 7.0 लाख रुपये का है।

Installation of Pesticides Formulation Plant in Maharashtra

727. SHRI RAMKRISHNA SADASHIV MORE: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Agro-Industries Development Corporation Ltd. has sent up proposals to Government of India for the installation of a pesticides formulation plant;